असली वेतन

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित

मूल्य १० पैसे

मजदूरों को असली वेतन चाहिए

मंहगाई भत्ता धोखा है

एक कहावत है 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' जो आज राज्य कर्मचारियों के ही नहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों और बड़े-बड़े निजी उद्योग के मजदूरों के भी विशाल आन्दोलनोपरान्त निकले हुए परिणाम से चरितार्थ हो रही है। मजदूर मांग करते हैं वह भी गलत आधार पर तथा संकोच के साथ। इतना ही नहीं उन मांगों के पूरा होने का उन्हें विश्वास भी नहीं रहता है। वे मांगते हैं तो केवल आँसू पोछने भर के लिये। उनकी आदत बनती जा रही है आधी रोटी मांगने की। मजदूर क्षेत्र में मंहगाई भत्ता बढ़ाओ नारा ही नहीं, वरन् विश्वास बनता जा रहा है। मजदूरों के प्रतिनिधि भी इस धोखे में फंसते जा रहे हैं। मजदूर नेताओं ने भी इस लकीर को कसकर पकड़ रखा है। वे मंहगाई के रोग से छुटकारा पाने के लिये मंहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी की मांग की मलहम पट्टी करना चाहते हैं। मंहगाई भत्ते की पद्धति अंग्रेजी शासन की देन है। मजदूर को आर्थिक गुलाम बनाकर रखने का यह कुचक्र है। विश्व के अन्य किसी भी देश में मंहगाई भत्ते की पद्धति नहीं है। मजदूर पूरे मास उत्पादन करता है उसके बदले में वेतन पाता है किन्तु महीने के इस वेतन को गलत ढंग से दो भागों में कर दिया है; जो आज २५ वर्षों से वेतन और मंहगाई भत्ते के नामों से अलग अलग दिया जाता है। यह पद्धति गलत है। इसे जितना जल्दी हम समाप्त करेंगे, मजदूर की भलाई उतनी ही जल्दी होगी।

मंहगाई भत्ता से वास्तविक वेतन की पूर्ति नहीं

निर्देशांक के अनुसार जिस समय मंहगाई भत्ता बढ़ता है, वह केवल भत्ता ही बढ़ता है, मूल वेतन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये मजदूर का वास्तविक वेतन घटता है। उदाहरण के लिये हम देखें—१९३९ से लेकर आज तक सामान्यतया मंहगाई ७ गुनी अधिक बढ़ गई है। अर्थात किसी कर्मचारी को यदि १९३९ में प्रतिवर्ष वेतन में एक रुपये की बृद्धि मिलती थी तो उसे इस समय प्रतिवर्ष सात रुपये की बृद्धि मिलनी चाहिये यदि किसी कर्मचारी का १९३९ में रु० ४४—२—८५ का ग्रेड था तो उसे आज रु० ३०८–१४–५९५ मिलना चाहिये। किन्तु मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन के दूने से अधिक कहीं नहीं है। और इस प्रकार प्रत्यक्षत: आज कुल वेतन रु० १३२—६—२५५ ही मिलता है। अर्थात हर मास उसे असली वेतन के हिसाब में १७६ से लेकर ३४० रुपये तक कम मिलता है। इतना ही नहीं उसके वेतन दर में ७ गुने की नहीं वरन ८ गुने की बढ़ोत्तारी होनी चाहिये। क्योंकि मजदूरों ने १९३९ की तुलना में आज तक उत्पादन में २० प्रतिशत की और बढ़ोत्तारी करदी है। सन् १९३९ में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ३० रु० था उसे आज के हिसाब के अनुसार २४० रुपये होना चाहिये। स्पष्ट है मंहगाई भत्ते की बढोत्तरी की मांग करके न तो हम उसे राष्ट्रीय न्यूनतम दिला सकते हैं और न वास्तविक वेतन ही। मंहगाई भत्ते से ८ रुपये की जिस मास में बृद्धि होती है तो दूसरी ओर उसी मास में परचून वाले का बिल १६ रुपये तक बढ़ जाता है। बाजारभाव बढ़ने की गति इतनी तीव्र है कि

मंहगाई भत्ते की मांग से हम उसे छू नहीं सकते। फिर हम इस दुष्चक्र (Vicious circle) में क्यों पड़ें। हम दुनिया के सामने इस विषय पर क्यों बदनाम हों कि कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की वृद्धि के कारण टैक्स बढ़ाने पड़े हैं। इस सफेद झूठ की भी बदनामी अपने ऊपर हम क्यों लें। हम तो न्याय चाहते हैं। परिश्रम की पूरी उजरत। हमें वास्तविक वेतन (Real wage) चाहिये।

मंहगाई भत्ता प्रथा—शोषण की ही प्रक्रिया है

प्रारम्भ में अंग्रेजों ने तथा स्वतन्त्रता के पश्चात कांग्रेस सरकार व पूंजीपतियों ने साठगांठ करके प्रावीडेन्ट फन्ड, ग्रैच्यूटी, पेन्शन व बोनस के पैसे बचाने के लिये मजदूरों को मूर्ख बनाकर वेतन और मंहगाई भत्ता अलग अलग रखा है। सौभाग्य है गत वर्ष के बोनस अधिनियम ने बोनस के मामले में मंहगाई भत्ते को भी वेतन के साथ जोड़ लिया है किन्तु शेष सभी भुगतान आज भी मूल वेतन के ही ऊपर आधारित है। इस कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये मजदूरों के हड़प लिये जाते हैं। इस लूट से बचने का एक ही रास्ता है हम वास्तविक वेतन की मांग करें।

वास्तविक वेतन न देने के अनेक बहाने

मजदूर को वास्तविक वेतन (*Real wage*) न देने का बहाना लेकर इस अपनी कही जाने वाली सरकार ने पूंजीपतियों के साठगांठ से वेतन का एक नया नाम निकाला कि मजदूरों को जीवन वेतन (*Living wage*) दिया जायगा किन्तु जब देश की बेकारी व भुखमरी की संख्या उन्हें दिखाई दी तो पुनः उसका नाजायज लाभ लेकर मजदूरों

के शोषण का उन्होंने विचार किया। इस जीवन वेतन को भी घटाकर उचित वेतन (*Fair wage*) नामकरण किया किन्तु इससे भी इन शोषण कर्ताओं की तृष्णा शान्त न हुई क्योंकि उनकी जिव्हा ने शोषण के रक्त का स्वाद ले लिया। अब वे उचित वेतन से हटकर प्रत्यक्ष वेतन (*Actual wage*) पर आ पहुंचे हैं, जिसको भी बिना आन्दोलन, हड़ताल के वे देने को तैयार नहीं। बेचारा मजदूर आज इसी आधी रोटी की लड़ाई में उलझ गया है।

मंहगाई भत्ता को वेतन में मिलाओ

हमारी मांग है कि आज की बदली हुई स्थिति में मजदूर के पारिवारिक बजट की नये सिरे से जांच हो। **देश के राज्यों के प्रमुख औद्योगिक नगरों से कम से कम एक एक सौ परिवारों के मासिक खर्चे निकाल कर आज का जीवन निर्देशांक निश्चित किया जाय। इस जांच में दाहसंस्कार, बेटी-बेटे के जन्म दिवस, विवाह, भोज, बच्चों की पढ़ाई, यातायात, कम्बल, रजाई, चारपाई, छाता, जूता, बर्तन आदि उन सभी खर्चों को जोड़ना पड़ेगा जिसको सरकार ने अभी तक आंखों से ओझल रखा है।** मंहगाई भत्ता अविलम्ब समाप्त करके उसका मूल वेतन के साथ विलीनीकरण कर दिया जाना चाहिये और उस सम्पूर्ण वेतन का सीधा सम्बन्ध इस नये सुधरे हुये जीवन निर्देशांक के साथ जोड़ देना चाहिये। इस प्रकार जो भी वेतन बनेगा वही मजदूरों का वास्तविक वेतन होगा। **मजदूरों को वास्तविक वेतन चाहिये तथा प्रत्येक उद्योग में अधिक से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी व कम से कम मजदूरी**

पाने वाले कर्मचारी के वेतन में १ और १० के अनुपात से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये ।

मंहगाई क्यों बढ़ती है ?

महगाई बढ़ाने वाले लोग प्रमुख रूप से व्यापारी और कारखानेदार हैं जो सरकार की ढीली पोली नीति से लाभ उठाते रहते हैं। वे ही वस्तुओं की कीमत निश्चित करते हैं पर जब भी उन पर यह आरोप लगाया जाता है तो वे सरकार की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने यातायात व बिजली का टैक्स बढ़ा दिया है। कच्चा माल व मशीन के पार्ट समय पर नहीं मिलते आदि ऐसे एक नहीं हजार बहाने बताते हैं उसी प्रकार जब सरकार पर आरोप लगाये जाते हैं तो वह व्यापारियों की ओर उंगली दिखाती है। पर उसे यह साहस नहीं कि उन व्यापारियों और उद्योगपतियों के विरुद्ध वह कार्यवाही करे। वास्तविक बात यह है कि सरकार व पूंजीपति दोनों ने मिलकर एक गिरोह बनाया है। सरकार स्वयं भी एक बड़ी सरमायेदार है। सहकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के सरकारी अधिकारी लाभ कमाने में व्यस्त है कीमतों की वृद्धि करने में उनका भी बड़ा भारी हाथ है। इस प्रकार अनेक प्रकार के नामधारण किये हुये ये सरमायेदार सामान्य जनता पर शासन चला रहे हैं व उन्हें लूट रहे हैं और उस पैसे से बड़े बड़े उद्योग धन्धे व बंगले खड़े कर रहे हैं। इतना अवश्य है कि यह सब करते समय बीच बीच में समाजवाद, समाजवाद का जाप भी करते रहते हैं। मालिकों के इस नये गुट के पास जिसमें सरकारी और निजीपूंजीपति दोनों हैं, गरीब का पैसा जा रहा है। बढ़ती हुई कीमतों के सभी पैसे इन्हीं की जेब में जमा हो रहे हैं।

आज रुपये के अवमूल्यन का ही उदाहरण लें। सरकार ने

रातोरात रुपये का अवमूल्यन करके बिना टैक्स लगाये, बिना चोरी डकैती किए मजदूरों के वेतन को दिल्ली में बैठे हुये ही कम कर दिया। वस्तुओं के दाम बढ़ गये पर वेतन न बढ़े। मजदूर के खरीदने की ताकत घट गई। गिनती का रुपया जैसा का तैसा पर उसकी कीमत कहीं एक चौथाई तो कहीं एक तिहाई कम हो गई। इस मूल्य बृद्धि का जिम्मेवार आखिर व्यापारी वर्ग ही है, जो कि सरकार के निकम्मेपन से लाभ उठाता रहता है।

अभी अभी रेल मंत्री श्री पाटिल साहब ने अपनी अलौकिकता प्रदर्शित करते हुये यह घोषणा की है कि सरकार शीघ्र ही ऐसे उपाय सामने ला रही है जिसमें वेतन और कीमतें दोनों स्थिर रहें। पूंजी-पतियों की इस सरकार के लिये लाठी गोली के सहारे भले ही कुछ दिनों के लिये वेतन का स्थिर करना सम्भव हो, पर कीमतों का स्थिर करना इसके वश का नहीं है और इसकी दिलीमंशा भी नहीं है। पाटिल साहब ने वेतन और कीमतें स्थिर करने की बात कहते समय आय और लाभ भी स्थिर किया जायगा की बात नहीं कह सके क्योंकि आय व लाभ की रेखा असीमित रखने में ही पूंजीपतियों के महल खड़े होते रहेंगे।

आन्दोलन आवश्यक

खुले आम चारो ओर से मजदूरों का शोषण हो रहा है। एक ओर बड़े बड़े होटल, क्लब, बंगले व कारें बढ़ रही हैं तो दूसरी ओर गरीबी बढ़ रही है। मंहगाई भत्ता इन सबका इलाज नहीं है। वास्तविक वेतन की प्राप्ति के लिये आन्दोलन करने होंगे। मंहगाई की तुलना में सम्पूर्ण वेतन बढ़े—ऐसी पद्धति निर्माण करने की मांग करनी पड़ेगी। मजदूरों के श्रम और पसीने की सच्ची कीमत ही उनका वास्तविक

वेतन है। वास्तविक वेतन का आन्दोलन ही इस रोग का रामबाण इलाज है। भारतीय मजदूर संघ ने समूचे देश में इस आन्दोलन को चलाने का निर्णय किया है। प्रत्येक राज्य में इस पवित्र एवं विशाल आन्दोलन की भिन्न भिन्न तिथियां निश्चित की गई हैं। उत्तर प्रदेश मजदूर संघ ने ३० अक्टूबर से ६ नवम्बर तक समूचे राज्य में प्रदर्शन, सभा व जुलूस आदि के माध्यम से 'असली वेतन मांग सप्ताह' मनाने का निर्णय किया है।

मुद्रक—टिप-टाप प्रिन्टर्स, २४/९१ बिरहाना रोड, कानपुर।